दिल्ली में शीघ्र ही पूर्वोत्तर सांस्कृतिक व सूचना केंद्र का निर्माण होगा-जितेन्द्र सिंह

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि दिल्ली में शीघ्र ही पूर्वोत्तर सांस्कृतिक व सूचना केंद्र का निर्माण होगा। उन्होंने आज यहां पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं के कार्यान्वयन की रूपरेखा विषय पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के पश्चात यह बात कही। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) के सचिव श्री नवीन वर्मा, पूर्वोत्तर परिषद के सचिव श्री राम मुइवा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पूर्वोत्तर के विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है और यह सांस्कृतिक केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए एक नए उपहार के समान है। डॉ. सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इस केंद्र का निर्माण नई दिल्ली के द्वारका में 1.32 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांस्कृतिक-सह-सम्मेलन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। मंत्री महोदय ने कहा कि इस केंद्र में पुस्तकालय-सह-अध्ययन कक्ष, एक कला दीर्घा, प्रदर्शनी हाल, शोध केंद्र, विक्रय केंद्र तथा अतिथि गृह होंगे। वर्तमान में इस परियोजना के भवन की रूपरेखा व डिजाइन, निर्माण की प्रक्रिया में हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 50 -55 करोड़ रुपये है। यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा।

बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्र देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक छात्रावास का निर्माण हो रहा है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की छात्राओं के लिए बैंग्लुरू विश्वविद्यालय में एक एक छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है।

भारत और सर्बिया में परस्पर विश्वास एवं समझ पर आधारित एक विशेष संबंध है-उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत और सर्बिया में परस्पर विश्वास एवं समझ पर आधारित एक विशेष संबंध है और दोनों देश 70 वर्षों के राजनयिक संबंधों का स्मरण करते हुए अपने ऐतिहासिक रिश्तों को लेकर गर्व का अनुभव करते हैं। वह आज यहां सर्बिया के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मामले मंत्री श्री इविका डेकिक के नेतृत्व में सर्बिया के शिष्टमंडल के साथ बातचीत कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने सर्बिया के उप प्रधानमंत्री को कोसोवो मुद्दे पर भरोसा दिलाया और कहा कि भारत के सैद्धांतिक पक्ष में कोई बदलाव नहीं आया है तथा वह कोसोवो की एकपक्षीय स्वतंत्रता की घोषणा (यूडीआई) को मान्यता नहीं देता। उन्होंने कहा कि भारत ने यूनेस्को, विश्व कस्टम संगठन (डब्ल्यूसीओ), इंटरपोल आदि समेत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सदस्यता के लिए कोसोवो के आवेदन का विरोध किया है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि सर्बिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सुधार लाने की असीमित गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि भारत और सर्बिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार हाल के वर्षों में बढ़ा है और यह बढ़कर 2017 में लगभग दो सौ मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भारत विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और यहां विभिन्न आर्थिक सुधार आंरभ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्बिया की कंपनियां बी-टू-बी मॉडल के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी का लाभ उठा सकती हैं।

उपराष्ट्रपति ने सर्बिया में योग की लोकप्रियता की सराहना की और पूरे सर्बिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के व्यापक आयोजन की प्रशंसा की।

आयुष्मान भारत पर राष्ट्रीय परामर्श-व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों का परिचालन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र के तकनीकी सहयोग से आयुष्मान भारत के तहत व्यापक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों को परिचालनगत करने पर दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में राज्यों के प्रमुख सचिव एवं एनएचएम के मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ज्ञान साझेदार, सीपीएचसी के नवोन्मेषण एवं अध्ययन केन्द्रों के प्रतिनिधि एवं विकास साझेदार शामिल थे। परामर्श समारोह की अध्यक्षता भी नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद पॉल, सचिव (स्वास्थ्य) श्रीमती प्रीति सूदान एवं एएस तथा एमडी के श्री मनोज झालान द्वारा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य एचडब्ल्यूसी को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल की प्रदायगी में सक्षम बनाने के लिए तथा प्रारूप परिचालनगत दिशा-निर्देशों के इनपुट प्राप्त करने के लिए विविध घटकों का एक साझा एवं समान समझ विकसित करना था। कार्यशाला की कार्रवाईयां व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न घटकों के पूर्वालोकन प्रस्तुतीकरण के साथ आरंभ हुई। इसमें मझोले स्तर के स्वास्थ्य प्रदाताओं जैसे प्रेरित प्रत्याशियों को चुनने एवं बहुद्देशीय श्रमिकों (पुरूष एवं महिला) एवं आशा समेत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम को सुदृढ़ बनाने के महत्व पर जोर दिया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में भरोसा एवं विश्वास पैदा करने और निजी खर्च में कमी लाने के लिए चयनित से व्यापक स्वास्थ्य देखभाल की तरफ रूपांतरण, पुरानी बीमारियों के लिए दवाओं की अबाधित उपलब्धता और देखभाल की सतत सुविधा उपलब्ध कराने के महत्व को भी रेखांकित किया गया। प्रस्तुतीकरण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सृजित मंचों की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया, जिनका प्रभावी रूप से उपयोग एचडब्ल्यूसी को परिचालनगत करने एवं उसे बढ़ावा देने में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, तपेदिक उन्मूलन की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पूर्ति करने के लिए एचडब्ल्यूसी में तपेदिक के लिए सक्रिय मामलों की खोजों को समेकित करने पर भी बल दिया गया ।

राज्यों के भागीदारों ने निम्नलिखित विषयों पर समूह बनाकर कार्य किया एचडब्ल्यूसी के लिए बुनियादी ढांचा एवं योजना निर्माण, मानव संसाधन, मध्य स्तर के स्वास्थ्य प्रदाताओं को संस्थागत बनाने, शहरी क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी के लिए आवश्यक इनपुट, रेफरल एवं देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आईटी प्रणलियों को कार्यशील बनाना, अनिवार्य दवाओं एवं नैदानिकी तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर को विस्तारित करना एवं वित्त पोषण। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों के लिए विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया। राज्यों से निश्चित समय सीमा निर्धारित करते हुए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं विकसित करने को कहा गया। कार्यान्वयन के पहले वर्ष में, राज्यों से चुने हुए प्रखंडों एवं जिलों में एचडब्ल्यूसी के रूप में सभी पीएफसी की प्राथमिकता तय करने को कहा गया, जहां बुनियादी ढांचा तथा मानव संसाधन का तंत्र पहले से ही मौजूद था। आकांक्षी जिलों से प्राथमिकता तय करने को कहा गया। एचडब्ल्यूसी (एचडब्ल्यूसी-एसएचसी) के रूप में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का समरूपी सुदृढ़ीकरण भी चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया जाएगा, जिससे कि 2022 तक 1,50,000 एचडब्ल्यूसी को परिचालनगत करने की प्रतिबद्धता की पूर्ति की जा सके। बहरहाल, इस बात पर जोर दिया गया कि गैर-संक्रमणीय रोगों की जांच, रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन, जो कि सीपीएचसी के तहत विस्तरित सेवाओं के पैकेज का एक हिस्सा है, पर एचडब्ल्यूसी-एसएचसी में व्यापक रूप से जोर दिया जाए, जिससे कि पुरानी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके।

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कोम्पलेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, एच-47, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया। फोन-26568477, 26409779. E : alpaviram1@yahoo.com

वायु सेना प्रमुख ने सीडब्ल्यूजी 2018 तथा आईएसएसएफ विश्व कप खेलो में पदक जीतने वाले वायु सेना कर्मियों को सम्मानित किया

वायु सेना प्रमुख बी एस धनोआ पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएम, एडीसी ने आज राष्ट्रमंडल खेलों (सीडब्ल्यूजी) 2018 तथा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ विश्व कप (आईएसएसएफ) खेलो में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 6 वायु सेना कर्मियों को सम्मानित किया।

इन अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में असाधारण प्रदर्शन के लिए वायु सेना कर्मियों की सराहना की गई। सीडब्ल्यूजी 2018 में जेडब्ल्यूओ विकास ठाकुर तथा सार्जेंट गुरु राजा ने भारोत्तोलन में (94 किलो वर्ग में) क्रमश: कांस्य और रजत पदक जीता। सीडब्ल्यूजी 2018 तथा आईएसएसएफ, मैक्सिको 2018 में जेडब्ल्यूओ रविकुमार ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता।

जेईई (मुख्य) परीक्षा 2018 में नवोदय विद्यालय के छात्रों का शानदार प्रदर्शन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति नवोदय विद्यालयों का संचालन करती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) 2018 में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आईआईटी/ एनआईआईटी (विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग तथा गणित में) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने आज एक ट्वीट के माध्यम से कहा, 'इस वर्ष नवोदय विद्यालयों के 4360 ग्रामीण छात्र जेईई एडवांस के लिए सफल घोषित किये गए हैं। जबकि पिछले वर्ष सफल छात्रों की संख्या 3653 थी। इस प्रकार सफल छात्रों की संख्या में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। छात्रों को बधाई। यह सफलता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार के फोकस को भी दर्शाती है।'

इस वर्ष 11653 नवोदय छात्रों ने जेईई (मुख्य) परीक्षा दी थी। इनमें से 4360 छात्र 20 मई, 2018 को होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। सफलता 37 प्रतिशत है जो किसी भी अन्य विद्यालय समूह से बेहतर है। जेईई एडवांस परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त 4360 में से 444 छात्रों ने एनवीएस के पूर्व छात्रों तथा स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से कोचिंग में पढ़ाई की थी।

शहर में राज्य की प्रथम अधिकृत 56 भोग परोसनेवाली रेस्टॉरेन्ट शुरू

अहमदाबाद : भगवान के सामने 56 भोग अर्पण किया जाता है और ग्राहक भी भगवान का दूसरा स्वरुप है, इसी बात को सार्थक करने अहमदाबाद में गुजरात की प्रथम अधिकृत 56 भोग परोसनेवाली रेस्टॉरेन्ट शुरू की गयी है। जिसमें लोगों को अनेक भारतीय खान-पान के व्यंजनों का स्वाद चखने मिलेगा। जिसमें राजस्थानी, काठियावाडी, पंजाबी, गुजराती जैसे अनेक प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होंगे। शायर रेस्टॉरेन्ट दी 56 भोग साइन्स सिटी रोड पर स्थित है।

शायर रेस्टॉरेन्ट दी 56 भोग के मालिक अमरसिंग चरण ने बताया कि हम लोगों ने इस रेस्टॉरेन्ट की शुरूआत करने से पहले कई स्थलों पर घुमें लेकिन हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम गुजरात की प्रथम ऐसी रेस्टॉरेन्ट है कि जो अपने ग्राहकों को अधिकृत 56 भोग परोसती है हमारे साथ अलग-अलग प्रकार की रसोई के अनुरूप उस स्थल के विशेषज्ञ रसौइयों की टीम है जिससे यहां आनेवाले प्रत्येक को उचित स्वाद चखने मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि भगवान को भोग लगाने के लिए भक्त 56 भोग अर्पण करते हैं । 56 भोग लगाने के पीछे एक कहानी हैं। कहा जाता है कि इन्द्र के प्रकोप से सभी बृजवासियों को बचाने के लिए उन्होंने गोवरधन पर्वत उठा लिया था। ऐसा करने के लिए उन्होने सात दिनो तक अन्न जल ग्रहण किया नही । सात दिन बाद गांव के प्रत्येक घर से उनके लिए 56 तरह के पकवान तैयार किये गये। तभी से भगवान को 56 भोग परोसा जाता है। (13-9)

आईएसएच इन्टरनेशनल प्रस्तुत करता है कूलसेन्स - पेइन नमबिंग एपलीकेटर

अहमदाबाद : जिन लोगों को बारबार इन्स्युलीन के इन्जेक्सन की जरूरत पड़ती है, बच्चें जो इनोक्युलेशन्स की बैट्री में जाते है अथवा ड्रॉप्स पर होते है, उनके लिए एक नविनता है जो स्टिंग इन्जेक्सन लेते है।

यह एक सामान्य भय है, जो ट्रीएनोफोबिया के रुप में जाना जाता है। भारत की आबादी के लगभग 10 प्रतिशत लोग इसके डर से पीड़ित है। इन्जेक्शन के लिए डॉक्टर्स के पास जाने के विचार से भयभित हो जाते है। कई डॉक्टर्स के ऑपरेशन को भी टॉलते है। अपने आप को विविध बीमारियों एवं संक्रमण के खतरे में डाल देते है। लेकिन इन्जेक्शन की डरानेवाली सुई के लिए संशोधको की टीम के पास जवाब है। उन्होंने इन्जेक्शन के दर्द को आसान बनाने के लिए एक नये उपकरण का विकास किया है।

मरीज की त्वचा को ठंडा करने के लिए तेजी से रसायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करके चमड़ी को शून्य कर दे, ऐसा अंश मिला है। सदियो तक रेखकांकन का निरुपण होना वह हेल्थकेयर प्रोफेशनल है जो दीर्घ अवधि तक एक सूई में नीडल को दाखिल करते हैं अथवा उंगली में वाइरस रह जाते हैं , जो कठोर और पीड़ा दायक है इ-कूलसेन्स के साथ लोग वर्च्युअल पीड़ा रहित तथा सरल प्रक्रिया का अनुभव कर सकते है।

इ-कूलसेन्स जो पेइन न्युम्बिंग एप्लीकेशन डिवाइस है जो पेरेन्ट कंपनी कूलसेन्स एलटीडी द्वारा विस्तृत आरएन्डडी के विकसित होने के बाद है। एक क्रांतिकारी सरल, हेन्ड हेल्ड डिवाइस , जो कोई भी रसायनिक इफेक्ट के बाद क्रेयो सिस्टम द्वारा इन्जेक्शन की साइट को एनेस्थेटीस करती हैं । इ कूलसेन्स का मुख्य उपक्रम में एक किटनाशक पद्धति का समावेश किया गया है, जिसमें अल्कोहोलिक जेल का समावेश होता है। जेल त्वचा को ठंडा - बर्न स्तर पर फैलती है जिससे अधिक सुरक्षा मिलता है। (19-8)

डीजीएफटी को नियामक के स्थान पर सुविधाप्रदाता बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए-सुरेश प्रभु

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु नई दिल्ली में बंदरगाह अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा आयोजित बंदरगाह अधिकारियों की दो दिवसीय बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए क्षेत्रीय अधिकारियों को संबोधित किया और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने नजरिये में बदलाव लाकर एक नियामक के स्थान पर एक सुविधाप्रदाता बनने की ओर अग्रसर हों। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने कामकाज को एक चुनौती और एक अवसर मानना चाहिए क्योंकि विदेश व्यापार अब भारत के लिए एक रणनीतिक मुद्दा हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि विदेश व्यापार से न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था लाभान्वित होती है, बल्कि यह देश को वैश्विक व्यापार से भी जोड़ता है। मंत्री महोदय ने निर्यात को नई गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय अधिकारियों की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने डीजीएफटी से लॉजिस्टिक्स सहित समस्त निर्यात संवर्धन मुद्दों पर राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति गठित करने का अनुरोध किया। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत डीजीएफटी के अधिकारियों को अनूठे उत्पादों की निर्यात संभावनाओं वाले जिलों की पहचान करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो अधिकारी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल साबित होंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

गर्मियों में इंटेक्स के एयर कंडीशनर्स की नई श्रृंखला लॉन्च की

अहमदाबाद, एयर प्योरिफिकेशन एवं पर्यावरण पर केंद्रण के साथ प्रमुख कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, इंटेक्स टेक्नॉलॉजीज़ ने आज एयर कंडीशनर्स की अपनी नई श्रृंखला लॉन्च की, जो ग्राहकों को ईको-फ्रेंडली रेफ्रिजरैंट्स-आर410ए एवं आर32 के साथ 'हेल्दी कूलिंग' प्रदान करेगी।

मिस. निधि मार्कन्डेय, डायरेक्टर-इंटेक्स टेक्नॉलॉजीज़ ने कहा, ''पिछले साल एयर कंडीषनर्स में हमारी षुरुआत को बाजार में बहुत पसंद किया गया और इस साल इंटेक्स ने एयर प्योरिफिकेषन एवं पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करके विभिन्न वैरिएंट पेष किए हैं, ताकि ग्राहकों को कूलिंग का हेल्दी अनुभव मिले। ग्राहकों पर केंद्रित दृश्टिकोण के साथ ईको-फ्रेंडली श्रृंखला एनर्जी एफिषियंट और इफेक्टिव तथा स्टाईल और एस्थेटिक्स में बहुत ऊपर है। कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स में एयर कंडीषनर सबसे कम विस्तृत श्रेणी है और टियर 2 एवं टियर 3 षहरों में प्रतिश्ठित ब्रांड होने के नाते इंटेक्स पर्यावरण के लिए मित्रवत किफायती श्रृंखला में अपनी एक अलग छाप छोड़ेगा।''

ईको फ्रेंडली एयर कंडीशनर तीन श्रेणियों-इंटेक्स इन्वर्टर स्प्लिट एसी, इंटेक्स फिक्स्ड स्प्लिट एसी और इंटेक्स विंडो एसी-में 14 मॉडलों में आते हैं। यह एफिशियंट, प्रभावशाली और इकॉनॉमिकल श्रृंखला 19,000 रु. से 35,000 रु. के बीच उपलब्ध है। (19-10)

श्रेय का संचयी षुद्ध लाभ (PAT) वित्त वर्श 2018 में 58% बढ़कर 384.55 करोड़ रु रहा

कोलकाता, भारत के सबसे बड़े समग्र इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थानों में से एक श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस लिमिटेड ("Srei") का संचयी कर उपरांत मुनाफा ("PAT") 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्श में उससे पिछले वित्त वर्श के 243.36 करोड़ रुपये के मुकाबले 58% बढ़कर 384.55 करोड़ रुपये रहा। एकल आधार पर कंपनी का कर उपरांत मुनाफा 2017-18 में 123.47 करोड़ रुपये रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्श में 96.07 करोड़ रुपये था।

31 मार्च, 2018 को खत्म हुई तिमाही के दौरान कंपनी का संचयी कर उपरांत मुनाफा इससे पिछले साल की समान तिमाही के 62.71 करोड़ रुपये की तुलना में 87% बढ़कर 116.98 करोड़ रुपये रहा।

31 मार्च, 2018 के समाप्त वित्त वर्श में कंपनी की कुल संचयी आय 5,261.87 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले साल 4,665.76 करोड़ रुपये रही थी।

31 मार्च, 2018 के अंत तक कंपनी के अधीन एकीकृत परिसंपत्ति प्रबंधन ("AUM") 47,050 करोड़ रुपये रहा, जो 31 मार्च, 2017 के अंत में 37,683 करोड़ रुपये था। 2017-18 में संचय ऋण आवंटन इससे पिछले साल के 17,604 करोड़ रुपये के मुकाबले 22,726 करोड़ रुपये रहा। (16)

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दर्शायी गयी तिथि में सील की गई खुली निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा संख्या :** एस.एण्ड.टी/बी.के.एन./ईटी 103 **कार्य का नाम व स्थान :** बीकानेर मण्डल के 32 स्टेशनों (रेवाड़ी-सादुलपुर-बीकानेर खंड) पर आर डी एस ओ द्वारा अनुमोदित ऑटोमैटिक फायर डिटक्सन एवं अलार्म सिस्टम का प्रावधान। **अनुमानित लागत मूल्य रू : 13987408/- बयाना राशि रू. : 219940/- निविदा प्रस्तुत करने की तिथि व समय :** 06.06.18 को 15.00 बजे तक। **वेब साइट जहॉ निविदा का पूरा विवरण देखा व डाउनलोड किया जा सकता है : www.ireps.gov.in** *485-AL/18*
रेल सुरक्षा संबंधी शिकायत हेतु हैल्पलाइन नं. 182 पर सम्पर्क करें

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दर्शायी गयी तिथि में सील की गई खुली निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा संख्या :** एस.एण्ड.टी/बी.के.एन./ईटी 102 **कार्य का नाम व स्थान :** बीकानेर मण्डल के 27 स्टेशनों (नाल-फलोदी, लालगढ़-भटिंडा तथा सुरतगढ़-हनुमानगढ़ वाया कनाल लूप खंड) पर आर डी एस ओ द्वारा अनुमोदित ऑटोमैटिक फायर डिटक्सन एवं अलार्म सिस्टम का प्रावधान। **अनुमानित लागत मूल्य रू : 11801875.50/- बयाना राशि रू. : 209010/- निविदा प्रस्तुत करने की तिथि व समय :** 06.06.18 को 15.00 बजे तक। **वेब साइट जहॉ निविदा का पूरा विवरण देखा व डाउनलोड किया जा सकता है : www.ireps.gov.in** *486-AL/18*
रेल यात्री सामान्य शिकायत हेतु हैल्पलाइन नं. 138 पर सम्पर्क करें

आपदा डेटाबेस पर कार्यशाला संपन्न, एनडीएमए ने राष्ट्रीय स्तर का आपदा डेटाबेस तैयार करने का मार्ग प्रशस्त किया

आपदा जोखिम न्यूनीकरण डेटाबेस के लिए डेटा संबंधी आवश्यकताओं पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज यहां सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इससे राष्ट्रीय स्तर का एक आपदा डेटाबेस तैयार करने अथवा सृजन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

स्थानीय स्तर पर प्राप्त एवं सत्यापित डेटा के साथ इस एकीकृत डेटाबेस को विकसित करना हमारे विभिन्न जोखिमों पर करीबी नजर रखने और इस मामले में सुदृढ़ स्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रगति करने के लिए अत्यंत आवश्यक है जिसके बिना भारत अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। यह डेटोबस आपदा जोखिमों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए 10 सूत्री एजेंडे के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसका उल्लेख नवंबर, 2016 में आयोजित डीडीआर पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीडीआर) में किया गया था।

इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (यूएनआईएसडीआर) के सहयोग से किया गया।

इस दौरान डेटाबेस में शामिल किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों, डेटा संग्रह टेम्प्लेट एवं डेटा एंट्री से जुड़े आईटी प्लेटफॉर्म, सत्यापन, प्रबंधन एवं विश्लेषण पर सामूहिक प्रस्तुतियां दी गईं और इसके साथ ही इन पर सामूहिक चर्चाएं भी हुईं।

इस कार्यशाला में हुई चर्चाओं से एक ऐसे संचालन समूह के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा जो इस डेटाबेस की स्थापना पर करीबी नजर रखेगा और इस डेटाबेस के परिचालन, रख-रखाव, अद्यतन एवं इस्तेमाल के लिए आवश्यक प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए मार्गदर्शन करेगा। यह समूह इसके अलावा पायलट (प्रायोगिक आधार पर) राज्यों को भी चिन्हित करेगा और इसके साथ ही परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक रूपरेखा या खाका (रोडमैप) भी तैयार करेगा।

एनडीएमए के पदाधिकारियों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई), आपदा प्रबंधन संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया।

सूचना
कृपया आपके विज्ञापन व समाचार हमारे निम्न लिखित ई-मेल पर ही भेंजे :
alpaviram@gmail.com